पुस्तकालय

1

2577
20/3/07

सत्यमेव जयते

16 MAR 2007 असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्रे०सं०...635...तिथि...20.07

बि० स० मु० (एल० ए०) 219--मोनो--1,000--9-6-2004

चतुर्दश विधान सभा

पंचम सत्र

१६ मार्च, २००७ ई०

शुक्रवार, तिथि ------------------------

२५, फाल्गुन, १९२८ (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-११.०० बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्षः अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।
अब अल्प-सूचित प्रश्न लिए जाएंगे ।

श्री भोला सिंहः अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न लें । हम जानना चाहते हैं आसन से कि सदन नेता ने इसी सदन में अपोजिशन से हार्दिक अपील की । उन्होंने आसन को सारी बातों के लिए सुपुर्द किया कि आसन जैसा चाहे, निर्णय करे । पांच दिनों से अपोजिशन भाग नहीं ले रहा है । उनके प्रश्न आते हैं, उनके कटौती के प्रस्ताव आते हैं, वह नहीं आ रहे हैं । सदन को यह जानने का अवसर दिया जाए कि क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे हैं ? आपके सद्प्रयास क्या हुए ? ये सारी बातें सदन का है ।

हम आग्रह करना चाहते हैं कि इस संबंध में सदन को अवगत कराया जाए ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, १२-००बजे इस विषय पर सरकार अपनी बात कहेगी ।

अध्यक्षः अल्प-सूचित प्रश्न । श्री रामचन्द्र पूर्वे ।

अल्प-सूचित प्रश्न संख्याः ४८(श्री रामचन्द्र पूर्वे)

(इस अवसर पर माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री रामचन्द्र पूर्वे अनुपस्थित।)

अल्प-सूचित प्रश्न संख्याः ४९(श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः १- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

२- यह बात सही है कि पीरपैंती, नवीनगर में क्रमशःचार-चार हजार मेगावाट, कुरसेला में दो हजार मेगावाट तथा बरौनी में अतिरिक्त पांच सौ मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है । परंतु वर्त्तमान में नवीनगर में दो हजार मेगावाट,पीरपैती में दो हजार मेगावाट एवं कटिहार में एक हजार मेगावाट प्रतिष्ठान प्रतिष्ठापित के लिए; लेकिन महोदय, परसों माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ जो एक बैठक हुई, उसमें

आइ०एल०एफ०एस०, जो भारत सरकार का एक फाइनान्सियल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको साइट सेलेक्ट करने के लिए और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए जो हमलोगों का पांच हजार मेगावाट होनी चाहिए, उसके लिए उनको ज़िम्मेवारी सुपुर्द करने का फैसला किया गया कि साइट भी सेलेक्ट करे, उसमें ख्याल रखा जाए कि उपजाऊ भूमि न लेकर के गैर-उपजाऊ भूमि पर ये प्रतिष्ठान स्थापित किए जाएं । साथ ही, कैमूर जिला में पांच पंप स्टोरेज जो पांच है उसमें एक, सिनासदारा जो है श्री इनटू एक सौ पंद्रह मेगावाट की स्वीकृति देकर के कैबिनेट में उसका प्रस्ताव करके एन०एच०पी०सी०, भारत सरकार से सहमति बन गई है कि भारत सरकार उसको बनायेगी । इसके अतिरिक्त, महोदय, कोशी में, जो बहुत पुराना था, चार इन्टु चार प्वायंट एट (४X४.८) मेगावाट का उसके लिए भी ३५ करोड़ का आवंटन दिया गया है जीर्णोद्धार के लिए, यह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का, महोदय, लक्ष्य था, फिर, कोशी हाइडल जो है २२६मेगावाट, उसमें एक बड़ी परियोजना, जो मेन कोशी रिभर में १२६ मेगावाट की है, उसको भी डिफरेंट इंटरनेशनल मोनटरी फंड, ए०डी०बी०, वर्ल्ड बैंक, अन्य एजेन्सी से भी उसको प्रपोज करने का है, तो यह ११वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग छः हजार मेगावट क्षमता की विस्तार का प्रस्ताव है।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, वैसे आज के जवाब में, और, कल भी सरकारी उत्तर में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया है। फिर भी, मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह जरूरी है कि तमाम परियोजनाओं में एन०टी०पी०सी० को ही लगाया जाए ! क्या और इस क्षेत्र में अगड़ी दूसरी कंपनियां, जो क्वालिटी के साथ काम करती हैं, उन्हें सरकार लगाने का विचार नहीं रखती? एन०टी०पी०सी० पर वैसे भी बहुत सारे काम का सारे देश में दबाव है, तो समय पर योजनाएं/परियोजनाएं पूरी हो जाएं, इस हेतु सरकार उस दिशा में कुछ ऐसे विकल्प और प्रकल्प हैं, उस पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-४९ का पूरक

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, ऐसा नहीं है कि एन०टी०पी०सी० को ही सारी परियोजनाएँ सुपुर्द की जा रही हैं लेकिन एन०टी०पी०सी० चूँकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक सहमति और भी है, एक प्रस्ताव और भी है कि नवीनगर में १३५० मेगावाट में एक यूनिट के लिए एन०टी०पी०सी० सहमत हो गई है, ५० परसेंट उसमें राज्य सरकार का शेयर रहे और ५० परसेंट उसमें एन०टी०पी०सी० अपना डोनेट करे और वह भी परियोजना बने । लेकिन ये फैसले अभी नहीं हुये हैं ।

लेकिन एक बात सच है महोदय, माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी तक प्राइवेट जो लोग हैं, इनर्जी सेक्टर में बहुत व्यापक पैमाने पर कोई अभिरूचि नहीं लिये हैं । अभी तक केवल भारतवर्ष में एक-दो यूनिट जो है, जो मेगा प्रोजेक्ट है ४ हजार मेगावाट का, उसमें एकाध में प्राइवेट इनवेस्टमेंट आया है तो सरकार की यह चाहत है कि प्राइवेट इनवेस्टर जब बहुत डिले कर रहे हैं, कोल ब्लॉक के भी उसके कई एक मामले हैं, फिर अन्य जो क्लीयरेंस है, सिविल एवियेशन का, फॉरेस्ट क्लीयरेंस, जिओलोजिकल ऑफ इंडिया क्लीयरेंस, फिर कोल का लिंकेज, रेल का लिंकेज - तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर इसको करती है तो उसमें सहुलियत होती है और जल्दी ही यूनिट आ जाती है । एन०टी०पी०सी० के साथ ही कोई ऐसा हमलोगों का एग्रीमेंट अभी तक हुआ नहीं है कि एन०टी०पी०सी० ही सारी करेगी । जैसा मैंने कहा कि जैसे- जल विद्युत का मामला है, तो एन०एच०पी०सी० जो ऑर्गेनाइजेशन है, वह अगर हमारे यहाँ कर देती है तो कोई एतराज नहीं है क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी परियोजना यह होगी ।

तो मुख्य रूप से हमलोगों का ऐसा नहीं है कि एन०टी०पी०सी० या एन०एच०पी०सी० या भारत सरकार का ऑर्गेनाइजेशन ही करे लेकिन अगर भारत सरकार का ऑर्गेनाइजेशन करे और बिजली हमारे राज्य में देने के लिए सहमति बन जाती है और हमारा भी इक्विटी शेयर हो और उनका भी इक्विटी शेयर हो तो उसमें एतराज का मामला नहीं बनता है । लेकिन प्राइवेट लोग भी अगर आयेंगे, जैसा मैंने कहा कि आई०एल०एफ०एस० जो है वह सारा क्लीयरेंस से लेकर कोल का भी लिंकेज, रेल का भी लिंकेज और पैसा भी उपलब्ध करवा देगा तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस तरह का एम०ओ०यू० करना लाभदायक होता है और पारदर्शिता भी रहती है और जल्दी यूनिट आ जाने की भी सम्भवाना रहती है । इसको मद्देनजर रखते हुये यह इरादा और सरकार का निर्णय की ओर इस मामले में इनक्लीनेशन ज्यादा रहता है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि पहला, इतना भारी पैमाने पर आने वाले दो-तीन वर्षों में उत्पादन का लक्ष्य हमलोगों ने रखा है और परियोजनाओं को हमने शुरू करने का मन बनाया है, तो उससे संबंधित क्षेत्रवार पूरे राज्य में ठीक से संचरण और आपूर्त्ति हेतु उस दिशा में तकनीकी दृष्टि से काम हो सके तो सब स्टेशनों का भी जाल बिछाना

पड़ेगा, उस दिशा में सरकार ने क्या योजना बनायी है और कितनी बिजली, जितना उत्पादन होगा उसमें हमारे राज्य के लिए, बिहार के लिए सुनिश्चित होगा ? हमारी क्या हिस्सेदारी होगी ? उसके लिए हमारी ओर से, सरकार की ओर से क्या कार्रवाई हुई है?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, कल भी मैंने जिक्र किया था कि ११२० मेगावाट हमारा अभी सेन्ट्रल शेयर में साझेदारी है और मैंने कल भी बताया था कि बरौनी और मुजफ्फरपुर जब हमारा रिनोवेट हो जायेगा तो हमारी क्षमता १५०० मेगावाट हो जायेगी । फिर स्टेज-५ जो सिक्किम में बन रहा है - तिस्ता, उसमें भी हमारा शेयर १२०-१२५ मेगावाट के करीब होगा और फेज-२ जो १५०२ मेगावाट का होगा उसमें २५०-३०० मेगावाट शेयर होगा और फरक्का का भी एक्सपेंशन हो रहा है और २००८ में बाढ़ का भी एक यूनिट आ जायेगा, उसमें भी शेयर होगा और नॉर्थ कर्णपुरा भी ११वीं पंचवर्षीय योजना में आने की उम्मीद है, जो उड़ीसा में तालचर है उसका भी एक्पेंशन हो रहा है, तो मिला-जुलाकर ११वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक यानी २०१२ तक, उसके मामले में हमको बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, जो चीनी मिले हैं वे भी आ जायेंगे लेकिन २०२० का जो लक्ष्य हमारा है कि उस समय में टोटल जो १०० परसेंट इलेक्ट्रिफिकेशन हर घर को देने का २०१२ का है और अन्य जो डिमांड बढ़ेगा उसको मीट करने के लिए ११वीं पंचवर्षीय योजना का हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हमने कल भी बताया था कि कोई भी परियोजना इनर्जी सेक्टर में ऐसा नहीं है कि आज हम करें तो तुरंत उसका परिणाम आ जायेगा, तीन-चार साल में आता है । इसलिये भविष्य का ख्याल रखते हुये २०२० के मिशन के तहत ये ५-६ हजार मेगावाट हम अपना बनाना चाहते हैं जो इस राज्य का हो और जिसमें अपना अधिकार हो । ...क्रमशः...

टर्न-३/आजाद/१६.३.२००७

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-४९ का पूरक क्रमशः

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : (क्रमशः) यही हमने बताया है । जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र की चर्चा की गई और ट्रांसमिशन के मामले में मैंने कहा था कि ५९२ करोड़ की परियोजना प्रथम चरण में पूरी हो गई, द्वितीय चरण को दो भागों में फेज-१ एवं २ में ६२९ करोड़ का एवं तृतीय चरण में भी केबिनेट ने १५११ करोड़ रू० का एप्रुवल दे दिया है । जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र का मामला है महोदय तो राजीव गाँधी योजना के तहत और ए०पी०डी०आर०पी० योजना के तहत लगभग पौने तीन हजार करोड़ रू० की परियोजना अगले २००९ तक में पूरी की जायेगी । अतिरिक्त भी जैसा मैंने कहा कि डिफरेंट इन्टरनेशनल मोनेटेरिंग ऑरगाईनेजेशन से और साथ-साथ इन्टरनल मोनेटेरिंग ऑरगाईनेजेशन जैसे पावर फाईनांस कॉरपोरेशन है, इनसे भी बातचीत चल रही है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ट्रांसमिशन सिस्टम में और भी जो नीड बेस्ड हमारा जो आकलन है, उसके अनुसार उसको कैसे एचीभ किया जाय, इस तरफ आगे बढ़ा जा रहा है । लेकिन जब निर्णय हो जायेगा तब ही फाईनल आऊट कम बताया जायेगा, सदन को बताना उचित होगा। यह सरकार दक्षित है अपने प्लान के मुताबिक, अपनी इच्छा के मुताबिक सारी परियोजनाओं में कि कल काई समस्या नहीं हो, इसका सारा आकलन करके सरकार आगे बढ़ रही है ।

श्री प्रेम रंजन पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के कम प्रस्ताव आते हैं लेकिन लखीसराय जिला में अभिजित ग्रुप ने १२१५ मेगावाट बिजली के लिए अपना प्रस्ताव दिया है । क्या माननीय मंत्री जी इसकी स्वीकृति देंगे लगाने के लिए ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, जहां तक इस मामले में बिहार सरकार की पॉलिसी है कि जो इनभेस्टमेंट बोर्ड है डेवलपमेंट कमीश्नर की अध्यक्षता में है, वहां लोग प्रस्ताव देते हैं, बोर्ड जो है उर्जा विभाग भी उसका सदस्य है, पूरा आकलन करके इसकी प्रक्रिया करती है और साथ ही भारत सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि मार्चेन्ट मीनी प्लांट जो है, वह अब ऑपेन हो गया है लेकिन जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, सबसे महत्वपूर्ण मामला यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को ही कोल ब्लौक का एरैजमेंट करना है । कई तरह की इसमें बातें हैं, कई तरह की क्लीयरेंस जैसा मैंने स्पष्ट किया कि तो कोल ब्लौक के मामले में भी बातें चल रही है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को कोल ब्लौक को अपने से हैंडिल करना पड़ेगा और अपने से उस काम को करना पड़ेगा । इसीलिए हमने कहा कि आई०एल०एफ०एस० को यह काम दिया गया है । वो अपना विभिन्न जगहों से होकर के फिर जब राज्य सरकार के पास प्रस्ताव आयेंगे और मार्चेन्ट प्लांट के लिए भी इनभेस्टमेंट बोर्ड उसको देखेगी । कोल लिंकेज और रेल लिंकेज ये दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इसको भी शोर्ट आऊट करके जब प्रस्ताव इनभेस्टमेंट बोर्ड के माध्यम से मोनेटेरिंग करके,

एसैसमेंट करके प्रस्ताव आवेगा तो सरकार उस पर सम्यक विचार करती है और उसको क्लीयर करने में एक मिनट, दो मिनट की भी देरी नहीं लगेगी ।

श्री लाल बाबू राय : अध्यक्ष महोदय, हमारा एक प्रश्न है । सारण जिला के मढ़ौरा में हमारे माननीय मंत्री जी गये थे चीनी मिल के उद्घाटन में तो जे०वी०जी० कम्पनी चीनी मिल जो है, वह २४ मेगावाट बिजली उत्पादन करने की बात इनके समक्ष कम्पनी के द्वारा स्वीकार की गई थी, जिसमें कम्पनी .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री लाल बाबू राय जी, जो प्रश्न है .....

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में माननीय सदस्य अवगत होंगे कि बिहार सरकार ने जो चीनी की पॉलिसी निर्धारित की है, उसमें जो भी इनभेस्टर हमारे यहां जितना भी मेगावाट विद्युत पैदा करेगा, हम ट्रांसमिशन लाईन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मुहैय्या करावेंगे और बिजली लेंगे । इसमें कही से कोई एतराज नहीं है, इसमें माननीय सदस्य को चिन्तित रहने की जरूरत नहीं है ।

श्री लाल बाबू राय : अध्यक्ष महोदय, वहां जनता का मांग था कि २४ मेगावाट में ८ मेगावाट बिजली कम्पनी खुद उपयोग करेगी और १६ मेगावाट .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामेश्वर प्रसाद जी । आपका अंतिम सवाल है ।

श्री रामेश्वर प्रसाद : महोदय, विद्युतीकरण का काम चल रहा है । अगले २ साल में करीब बिहार को चार हजार, पाँच हजार मेगावाट की जरूरत होगी और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि प्राइवेट इनभेस्टर अभी रूचि ज्यादा नहीं दिखायी दे रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सिर्फ कैमूर रेंज में दुर्गावती प्रोजेक्ट के अलावे भी सर्वे हुआ था, उसमें तीन हजार मेगावाट पनबिजली की क्षमता है । क्या मंत्री महोदय, क्या राज्य सरकार इसमें अपने स्तर से वहां बिजली पैदा करना चाहती है, अगर प्राइवेट इनभेस्टर नहीं आ रहे हैं तो क्या इसकी कोई योजना है, अगर नहीं है तो जो बिजली की कमी होगी, उसको आप कैसे पूरा करेंगे ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, तीन हजार मेगावाट की क्षमता का आकलन का कोई ब्यौरा सरकार के पास अभी उपलब्ध नहीं है । लेकिन इन्द्रपूरी में जैसा मैंने कहा कि कैमूर में २५०० मेगावाट पम्प स्टोरेज स्कीम है, अब उसका डी०पी०आर० तैयार हो रहा है, साथ ही इन्द्रपूरी का मामला मध्यप्रदेश,उत्तरप्रदेश, झारखंड और बिहार से संबंधित है । झारखंड राज्य की सहमति है, मध्यप्रदेश की भी सहमति है लेकिन उत्तर प्रदेश ने अपना एक पावर प्लांट लगा लिया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के आनाकानी के चलते यह काम रूका हुआ है ।

(क्रमशः)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-४९ का पूरक(क्रमशः)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जहाँतक और मामले हैं कि १६ नदियों का जैसाकि मैंने कल भी जिक्र किया था कि १६ नदी, गंगा और कोशी को छोड़कर जो हमारे यहाँ अवस्थित है, एन०एच०पी०सी० की एक टीम, पांच सदस्ययी उसका टोटल एसेसमेंट कर रही है । एसेसमेंट जब कम्पलिट होगा तो तब पता चलेगा कि उसमें कितनी संभावना बिहार में हाईडल पोटेंशियल की है तो उसपर भी सरकार आगे बढ़ रही है और काम आगे चल रहा है ।

अध्यक्ष : अब अल्पसूचित प्रश्न समाप्त हुए, तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-४१०, माननीय सदस्य श्री रमई राम

श्रीमती पूनम देवी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रमई राम जी आये हुए थे और आपको लिखित दिये है और हमको भी कहे थे कि देख लीजियेगा ।

अध्यक्ष : बैठिए, माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के अनुसार वर्ष २००३-०४ की जगह वर्ष २००५-०६ समझा जाय ।

खंड(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

अप्रील, २००६ में कार्यपालक अभियन्ता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को प्राक्कलन समर्पित करने का निदेश दिया गया है ।

खंड(3) प्राक्कलन निर्माण और इसकी तकनीकी स्वीकृति का विषय कार्यपालक अभियन्ता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं अधीक्षण अभियन्ता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर के स्तर पर लम्बित है ।

खंड(4) सक्षम पदाधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन प्राप्त होने पर प्रशासनिक स्वीकृति के बाद आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

श्रीमती पूनम देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि पेनटून पुल का जीर्णोद्धार एवं विस्तार करने की स्वीकृति के संबंध में जैसाकि अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि उत्तर स्वीकारात्मक है खंड-१ एवं २ का, तो अभीतक स्वीकृति मिलने के बाद इसका टेंडर क्यों नहीं हुआ ? अगर टेंडर नहीं हुआ, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने अभी अपने जबाब में बताया है कि कार्यपालक अभियन्ता को आदेश दिया गया था, लेकिन कार्यपालक अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के स्तर पर लम्बित रहने के वजह से ही समय पर टेंडर नहीं हो सके, जिसके कारण इस कार्य में विलम्ब हो रहा है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है । इस तरह से लापरवाही बरती रहे हैं पदाधिकारी तो मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि जिन पदाधिकारियों का इसमें लापरवाही बरतने का हाथ है, उसके उपर सरकार क्या कारवाई करना चाहती है और कबतक यह पुल बनेगा ?